सांध्य दैनिक
4PM
जिद...सच की
मूल्य ₹ 3/-
www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_SanjayS YouTube @4pm NEWS NETWORK
● वर्ष: 11 ● अंक: 312 पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, शनिवार 20 दिसम्बर, 2025

यदि आप हमेशा गुस्सा या शिकायत करते हैं तो लोगों के पास आपके लिए समय नहीं रहेगा।
-स्टीफन हॉकिंग

भारत का लगातार सातवीं टी20 सीरीज... 7
अब नेहरू के दस्तावेजों पर सियासी... 3
भाजपा जब खुद फंसती है तो... 2

ट्रंप का सस्ता दवा बम भारत के फार्मा साम्राज्य पर सीधा वार ?

भारतीय दवा कंपनियों के मुनाफे पर गहरी चोट

» मोदी-ट्रंप रिश्तों में बढ़ती तल्खी का एक और संकेत

» भारतीय दवा कंपनियों के शेयरों पर पड़ सकता है उल्टा असर!

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दवाओं की कीमतों में भारी कटौती का ऐलान कर न सिर्फ अमेरिकी फार्मा उद्योग को झकझोर कर दिया है बल्कि भारत जैसे देशों की दवा अर्थव्यवस्था को भी अनिश्चितता के भंवर में डाल दिया है।

ट्रंप का दावा है कि अब अमेरिकी नागरिक दुनिया में कहीं भी मिलने वाली सबसे कम कीमत से ज्यादा दाम दवाओं के लिए नहीं चुकाएंगे। पहली नजर में यह फैसला अमेरिकी जनता के लिए राहत भरा दिखता है लेकिन इसके दूरगामी असर वैश्विक दवा बाजार खासकर भारत के जेनेरिक दवा निर्यात पर पड़ने तय माने जा रहे हैं।

भारत की कंपनियों पर पड़ेगा निगेटिव असर

ट्रंप के फैसले का सबसे पहला और सीधा असर भारतीय दवा कंपनियों के मुनाफे पर पड़ेगा। अमेरिका पहले से ही दवाओं की कीमतें घटाने का दबाव बना रहा है। अब सरकार खुद कीमत तय करने या अंतरराष्ट्रीय तुलना के आधार पर दाम कम करने की बात कर रही है। इससे भारतीय कंपनियों को और सस्ते दाम पर दवाइयां सप्लाई करनी पड़ सकती हैं। सन फार्मा, डा. रेड्डी, सिपला, लयूपिन जैसी कंपनियां अमेरिकी बाजार पर अत्यधिक निर्भर हैं। कई कंपनियों की आधी से ज्यादा कमाई अमेरिका से आती है। कीमतों में कटौती का मतलब है कि मार्जिन और पतले होंगे। इसके साथ ही एफडीए की सख्ती निरीक्षण और संभावित चेतावनी पत्रों का जोखिम भी बढ़ सकता है। छोटी और मझोली भारतीय कंपनियों के लिए यह स्थिति और कठिन हो सकती है, क्योंकि उनके पास न तो बड़े पैमाने की ताकत है और न ही लंबे समय तक नुकसान झेलने की क्षमता। शेयर बाजार में भी इस घोषणा के बाद फार्मा सेक्टर में अस्थिरता देखी जा सकती है।

दवाइयों का अर्थशास्त्र

दवाइयों का अर्थशास्त्र सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं से बिल्कुल अलग होता है। यहां कीमतें लागत से नहीं बल्कि पेटेंट, रिसर्च, ब्रांड वैल्यू और रेगुलेटरी ताकत से तय होती हैं। अमेरिका में दवाइयों की कीमतें इसलिए ऊंची हैं क्योंकि वहां पेटेंट संरक्षण मजबूत है और सरकार को दवा कंपनियों से सीधे मोलभाव का अधिकार लंबे समय तक नहीं मिला। इसके उलट भारत में पेटेंट कानून अपेक्षाकृत लचीले हैं जिससे जेनेरिक दवाओं का उत्पादन संभव हुआ। यही कारण है कि भारत की वही दवाएं अमेरिका की तुलना में 80-90 प्रतिशत सस्ती होती हैं। ट्रंप इसी अंतर को खत्म करना चाहते हैं लेकिन यह अंतर मिटाने की कोशिश वैश्विक दवा व्यापार के संतुलन को बिगाड़ सकती है।

मोदी-ट्रंप के बीच बढ़ती तनातनी

मोदी और ट्रंप के रिश्ते सार्वजनिक मंचों पर भले ही दोस्ताना दिखते हो लेकिन व्यापार के मोर्चे पर दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ा है। अमेरिका पहले ही भारत को व्यापार में टैरिफ किंग कह चुका है। स्टील, एल्युमिनियम, आईटी सर्विसेज और अब दवाइयां हर मोर्चे पर अमेरिका भारत से रियायत चाहता है। दवाओं का मुद्दा इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि भारत की सस्ती दवाइयां अमेरिकी कंपनियों के मुनाफे को चुनौती देती हैं। ट्रंप का यह फैसला संकेत देता है कि वे अब सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि भारत जैसी उभरती आर्थिक ताकतों को भी दबाव में लाना चाहते हैं। यह नीति मोदी सरकार के लिए कूटनीतिक रूप से असहज स्थिति पैदा कर रही है।

700 परसेंट तक सस्ती होंगी दवाइयां

ट्रंप ने यह घोषणा स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े शीर्ष अधिकारियों और दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में की। उन्होंने कहा कि दशकों से अमेरिकी नागरिकों को दुनिया की सबसे महंगी दवाएं खरीदने को मजबूर किया गया और अब इस लूट को खत्म किया जाएगा। ट्रंप का दावा है कि कई दवा कंपनियां कीमतों में 300 से 700 प्रतिशत तक की कटौती पर सहमत हो चुकी हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर विदेशी सरकारें दवाओं की कीमतें कम नहीं करती है तो अमेरिका टैरिफ जैसे हथियारों का इस्तेमाल करेगा।

सवाल

यह है कि क्या ट्रंप का यह कदम सिर्फ अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए है या फिर यह भारत जैसी उभरती दवा ताकतों को नियंत्रित करने की रणनीति का हिस्सा है?

कितना बड़ा है यह बाजार

वैश्विक फार्मा बाजार का आकार लगभग 1.5 ट्रिलियन डालर का है। अकेले अमेरिका इसमें करीब 550-600 बिलियन डालर का हिस्सा रखता है यानी दुनिया का सबसे बड़ा दवा बाजार। भारत का फार्मा उद्योग लगभग 50 बिलियन डालर का है जिसमें से बड़ा हिस्सा निर्यात का है। अमेरिका भारत के कुल दवा निर्यात का लगभग 30-35 प्रतिशत आयात करता है। ऐसे में अमेरिकी नीति में जरा-सी सख्ती भी भारतीय दवा कंपनियों के लिए बड़ा झटका बन सकती है।

दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है भारत

यहीं से भारत की चिंता शुरू होती है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा जेनेरिक दवा उत्पादक और निर्यातक है। अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़ा दवा निर्यात बाजार है, जहां भारत की सस्ती जेनेरिक दवाओं ने अमेरिकी स्वास्थ्य व्यवस्था को लंबे समय तक संभाला है। लेकिन ट्रंप का नया फार्मूला मोस्ट फेवरेट नेशन प्राइस भारत की इसी ताकत को उसके लिए कमजोरी में बदल सकता है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप का यह कदम सिर्फ अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए है या फिर यह भारत जैसी उभरती दवा ताकतों को नियंत्रित करने की रणनीति का हिस्सा है? क्या यह फैसला भारतीय दवा कंपनियों के मुनाफे पर सीधा हमला है? और क्या यह मोदी-ट्रंप रिश्तों में बढ़ती तल्खी का एक और संकेत है। इन सवालों के जवाब केवल दवाओं की कीमतों में नहीं बल्कि दवाओं के वैश्विक अर्थशास्त्र, व्यापार युद्ध, कूटनीति और मुद्रा बाजार में छिपे हैं। ट्रंप का यह फैसला आने वाले समय में यह तय करेगा कि भारत दुनिया की फार्मेसी उद्योग में लीड करता रहेगा या नहीं । अमेरिकी नीति के सामने उसे अपने माडल पर दोबारा विचार करना पड़ेगा।

भाजपा जब खुद फंसती है तो दूसरों को फंसाती है : अखिलेश यादव

सीएम योगी के बयान पर सपा प्रमुख का पलटवार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। कफ सिरप मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है। उन्होंने एक्स पर शायराना अंदाज में कहा... जब खुद फंस जाओ, तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, ये खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नई बात बताओ। सपा अध्यक्ष आगे दोनों डिप्टी सीएम और सीएम का फोटो लगाते हुए कहते हैं ...फुल दो हॉफ हैं, यूं तो आपस में खिलाफ हैं। कोडीन के मारे ये सारे, आज डर के मारे साथ हैं। अखिलेश ने कहा कि नशाखोरी की जांच के लिए सिरप टॉस्क फोर्स मतलब एसटीएफ के साथ-साथ जीटीएफ भी बना दीजिए। बाकी जनता समझदार है।

भाजपाइयों के चेहरों पर हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं। कोडीन कफ सिरप की सच्चाई वे जानते हैं, तभी खुद नहीं पी, इसीलिए बीच में किसी को खांसी भी आ गई। अखिलेश यादव ने कहा कि अवैध और जहरीली कफ सिरप मामले की जांच कर रही एसटीएफ भी अवैध कारोबारियों से मिली हुई है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। विधानमंडल सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग ऑक्सीजन सिलेंडर और कोडीन कफ सिरप को पोस्टर लेकर विधानसभा पहुंचे। सपा के अन्य विधायक भी कफ सिरप का पोस्टर पहनकर आए। जाहिद बेग ने आरोप लगाया कि प्रदूषण की गंभीर स्थिति के चलते एक अंतरराष्ट्रीय मैच तक रद्द करना पड़ा, जो सरकार की विफलता को दिखाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है।

दो करोड़ नाम जोड़ने का चुनाव आयोग पर दबाव

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स के माध्यम से कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग पर अगले दो महीनों में 2 करोड़ मतदाताओं का नाम फॉर्म 6 के माध्यम से जोड़ने के लिए दबाव बनाने की जो बात चर्चा में है, भाजपा सरकार उसका स्पष्टीकरण दे। जब एसआईआर चल रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 3 करोड़ मतदाताओं के नाम काटने की बात स्वयं मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो फिर चुनाव आयोग बताए कि फॉर्म 6 के माध्यम से 2 करोड़ नए मतदाता कहां से लाए जा रहे हैं।

न्यायालय स्वतः संज्ञान लेकर एसआईआर पर कार्रवाई करे

उन्होंने सवाल उठाया कि क्या बीएलओ पर फिर से दबाव बनाया जा रहा है। जब एसआईआर चल रहा है तो फॉर्म 6 के लिए दबाव क्यों बनाया जा रहा है। ये बेहद गंभीर मामला है, इस सिलसिले में जो फोन करवाए जा रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग जिनके पास है, उनसे आग्रह है कि देशहित में वो इसको जारी करें। न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और तत्काल कॉल रिकॉर्ड प्राप्त करके दंडात्मक कार्रवाई करे।

फसल बीमा घपले की हो सीबीआई जांच : वंशराज दुबे

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। आम आदमी पार्टी (आप) ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बुंदेलखंड में की गई गड़बड़ी की जांच कराने की मांग की है। इतना ही नहीं जांच स्थानीय स्तर पर नहीं, बल्कि सीबीआई या उच्च न्यायालय के वर्तमान जज की निगरानी में कराई जाए। दोषी अधिकारियों और बीमा कंपनियों के प्रबंधकों से इसकी रिकवरी की जाए।

आप ने भाजपा पर किया हमला

आप के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता वंशराज दुबे ने प्रदेश मुख्यालय पर प्रेस वार्ता में कहा कि यह बहुत बड़ी गड़बड़ी है। पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विशेष ऑडिट कराया जाए, क्योंकि बुंदेलखंड केवल एक बानगी मात्र है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के संरक्षण में बीमा कंपनियों, अधिकारियों और दलालों की मिलीभगत से कागजों पर खेती उगाई गई। वंशराज दुबे ने कहा कि रेलवे पटरियों और सरकारी जमीनों पर फसल दिखाकर करोड़ों का घोटाला किया गया। जबकि असली किसान सूखे और कर्ज में दम तोड़ रहा है। महोबा के लुहारी गांव का कुल रकबा 747 हेक्टेयर है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड और बीमा दस्तावेजों में 1138 हेक्टेयर भूमि का बीमा दिखा दिया गया।

इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी बिना विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के संभव ही नहीं है। 52 हजार पॉलिसियों का निरस्त होना इस बात का खुद सबूत है कि यह तंत्र कितना गहरा और संगठित है। ऐसे में इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई? कृषि मंत्री केवल कार्रवाई होगी कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं। इस गड़बड़ी की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कृषि मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो पार्टी इस मुद्दे को सड़क से सदन तक ले जाएगी।

नीतीश की हरकत धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला : बर्क

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक महिला डॉक्टर के चेहरे से बुर्का हटाने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह अफसोसजनक है कि देश बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहा है, और नीतीश कुमार ने अपने कृत्य के लिए माफी तक नहीं मांगी है।

बुर्का विवाद में सपा सांसद ने भाजपा को घेरा

जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह अफसोसजनक है कि एक मुस्लिम महिला के साथ ऐसी घटना के बाद भी देश विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहा है। उन्होंने न तो माफी मांगी है और न ही कोई कार्रवाई की गई है। इससे पहले, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने हिजाब और बुर्का को महिलाओं के सम्मान, गरिमा और गौरव का प्रतीक और उनके सिर का ताज बताते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कड़ी आलोचना की। पठान ने उन पर महिलाओं की गरिमा और संवैधानिक अधिकारों का अपमान करने का आरोप लगाया। एएनआई से बात करते हुए पठान ने मुख्यमंत्री से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की और इस घटना को महिलाओं की मर्यादा और धार्मिक स्वतंत्रता का घोर उल्लंघन बताया।

होलिका दहन और दाह संस्कार से भी प्रदूषण : आरके चौधरी

सपा सांसद के बयान से बीजेपी आगबबूला

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के सांसद आरके चौधरी ने होलिका दहन पर अपनी टिप्पणी का बचाव करते हुए कहा कि हिंदू भावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो जाएगा। मोहनलाल गंज से लोकसभा सांसद ने यह भी कहा कि देश में प्रदूषण कम करने के लिए पेड़ लगाना ही एकमात्र उपाय नहीं है। उन्होंने कहा कि पेड़ लगाने से प्रदूषण कम नहीं होगा, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है।

होलिका दहन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हैं। इसलिए, अगर हम हिंदू भावनाओं को ध्यान में रखेंगे, तो प्रदूषण पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो जाएगा। चौधरी ने कहा कि शवों को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें निकलती हैं, जो प्रदूषण में बहुत योगदान देती हैं। उन्होंने होलिका दहन त्योहार का भी जिक्र करते हुए कहा कि वायु प्रदूषण का मुद्दा धर्म से नहीं, बल्कि पर्यावरण से जुड़ा है। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि शवों को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती हैं, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन कम हो जाती है। होलिका दहन के दौरान भी होलिका दहन में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती हैं। हमारा देश वायु प्रदूषण को लेकर गंभीर नहीं है।

चौधरी को अपना धर्म बदल लेना चाहिए : गिरिराज सिंह

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने चौधरी की टिप्पणियों को लेकर समाजवादी पार्टी की कड़ी आलोचना की है। भगवा पार्टी की ओर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने चौधरी पर हमला बोलते हुए कहा कि चौधरी को अपना धर्म बदल लेना चाहिए। भाजपा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने भी चौधरी की आलोचना करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के सांसद वायु प्रदूषण के मुद्दे पर हिंदुओं पर हमला करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे वाहनों और पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को नहीं देख पा रहे हैं, वे सिर्फ हिंदू धर्म पर हमला करना चाहते हैं, इसीलिए वे ऐसे भ्रामक बयान दे रहे हैं। यह बहुत दुखद है।

पूरा ध्यान दें वोटर लिस्ट से वंचित न रहें : मायावती

बसपा ने राज्यवार रिपोर्ट की समीक्षा की

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ । बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को तत्परता से पूरा करने के निर्देश दिए। वह आल इंडिया बैठक की अध्यक्षता कर रहीं थीं। बैठक में यूपी व उत्तराखंड को छोड़कर अन्य राज्यों के पदाधिकारियों शामिल हुए।

मायावती ने कहा कि पार्टी के अन्य संगठनात्मक कार्यों को कुछ समय के लिए स्थगित कर इस अभियान पर फोकस करें, ताकि गरीब, मजदूर व बहुजन समाज के लोग वोटर लिस्ट से वंचित न रहें। मायावती ने राज्यवार रिपोर्ट की समीक्षा की। इस दौरान संगठन की मजबूती, जनाधार बढ़ाने व आर्थिक सहयोग पर पिछली बैठकों के निर्देशों का पालन न होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कमियों को जल्द दूर करने को कहा। स्ट्रक्के दौरान हो रही परेशानियों का जिक्र कर अन्य राज्यों को पहले से तैयारी करने की सलाह दी।

चुनावी व्यवस्था पर उठाए सवाल

मायावती ने कहा कि वोटर लिस्ट शुद्ध करने के साथ धनबल, बाहुबल व सरकारी हथकंडों से मुक्त चुनाव की जरूरत है। बिहार चुनाव में सरकारी धन वितरण से प्रभावित करने के प्रयास को गंभीर बताया। मनरेगा की जगह प्रस्तावित विकसित भारत ग्रामीण रोजगार योजना में केंद्र के अंश घटाने की आलोचना की।

जनकल्याणकारी दिवस के रूप में मनेगा बहनजी का जन्मदिन

15 जनवरी को बहनजी का जन्मदिन जनकल्याणकारी दिवस के रूप में मनाने के निर्देश दिए। यूपी में मंडल स्तर, अन्य राज्यों में जोन स्तर पर कार्यक्रम होंगे। बीएसपी सरकार के जनहित कार्यों व महापुरुषों के सम्मान की चर्चा कर बहुजनों को प्रेरित करने को कहा। बैठक में पदाधिकारियों का धन्यवाद दिया।

अब नेहरू के दस्तावेजों पर सियासी घमासान

गजेंद्र शेखावत ने सोनिया गांधी से की ऐतिहासिक कागजात लौटाने की अपील

» भाजपा ने कांग्रेस पर किया हमला

» पीएमएमएल को कागजात देने को कहा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। लगता है भाजपा नेहरू के नाम पर सियासत छोड़ना नहीं चाहती है। संसद के अंदर से लेकर बाहर तक बीजेपी नेताओं के मुंह पर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू चढ़े रहते है। अब पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू से जुड़े दस्तावेजों का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है।

केंद्रीय गजेंद्र सिंह शेखावत ने उन दस्तावेजों पर सवाल उठाया है, जो 2008 में प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय से लिए गए थे। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से देश की दस्तावेजी विरासत को बचाने के लिए इन कागजात को वापस लौटाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि 1971 से 1992 के बीच नेहरू से संबंधित करीब 4 लाख दस्तावेज 9 अलग-अलग मौकों पर पीएमएमएल को सौंपे गए थे। जिन्हें सरकार को सुरक्षित रखने के लिए रखा गया था, न कि उपहार के तौर पर किसी को देने के लिए।

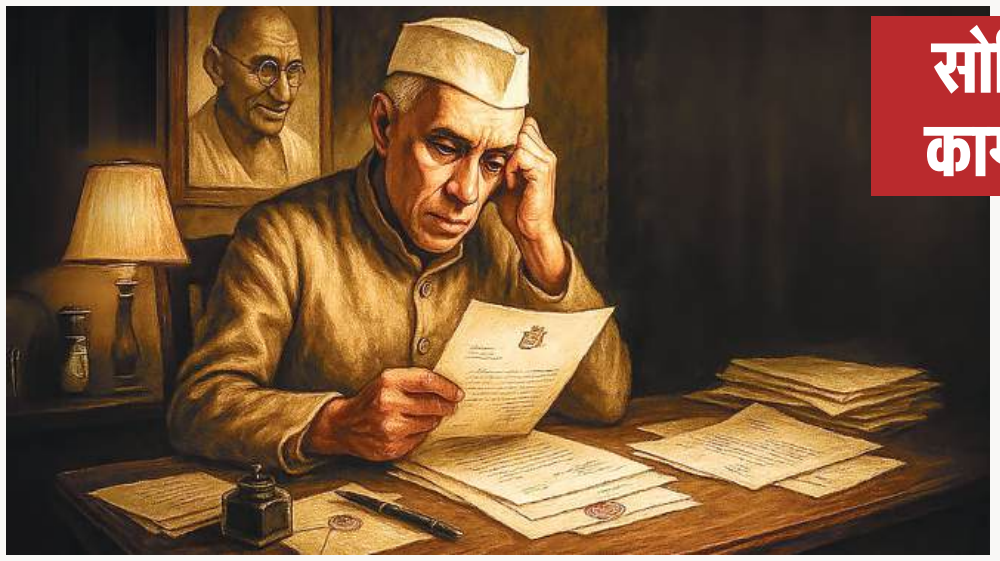

सोनिया ने नेहरू से जुड़े कागजात वापस लिए थे

केंद्रीय मंत्री ने सोनिया गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा, कि 2008 में, गांधी परिवार ने जवाहरलाल नेहरू से जुड़े कागजात वाले 51 बॉक्स, को पीएमएमएल से वापस ले लिया था। उन्होंने बताया कि ये दस्तावेज 2008 में विधिवत प्रक्रिया के तहत गांधी परिवार को सौंपे गए थे और पीएमएमएल में इनके रिकॉर्ड व कैटलॉग मौजूद हैं। लेकिन मूल प्रश्न यह है कि क्यों इन दस्तावेजों को अब तक वापस नहीं किया गया, जबकि पीएमएमएल की ओर से इस बारे में कई बार पत्र भेजे गए। विपक्ष के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि नेहरू से संबंधित कोई भी दस्तावेज लापता नहीं है, क्योंकि उनकी जानकारी है। मंत्रालय ने इन कागजात को राष्ट्र की दस्तावेजी विरासत का हिस्सा बताते हुए इन्हें वापस करने की मांग की है।

एम.वी. राजन ने लिए थे कागजात

संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के अनुसार, 29 अप्रैल 2008 को एम.वी. राजन ने सोनिया गांधी के प्रतिनिधि के तौर पर नेहरू के निजी पारिवारिक पत्रों और नोट्स को वापस लेने का अनुरोध किया था। इसके बाद 2008 में नेहरू के कागजात के 51 कार्टन सोनिया गांधी को भेजे गए थे। पीएमएमएल लगातार सोनिया गांधी के कार्यालय से इन कागजात की वापसी के लिए पत्राचार कर रहा है, जिसमें 28 जनवरी 2025 और 3 जुलाई 2025 के पत्र भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी के सदस्य और इतिहासकार रिजवान कादरी ने भी उम्मीद जताई है कि सोनिया गांधी इन संग्रहों को वापस कर देंगी।

ये है मामला?

कार रिजवान कादरी ने बताया कि 2019 में उन्हें सोसाइटी में नियुक्त किया गया था और शोधकर्ताओं की सुविधा के लिए प्रयास किए गए। उन्होंने एडविना माउंटबेटन के कागजात का अध्ययन करने की कोशिश की थी, जो उनकी बेटी ने संस्था को दान किए थे, लेकिन वे उन्हें देख नहीं पाए थे। यह मुद्दा वार्षिक आम बैठक में उठाया गया था और सोनिया गांधी ने ये कागजात अपनी कस्टडी में ले लिए थे। कादरी ने कहा कि 2024 की बैठक के बाद, पहली बार संस्था के मिनट्स में यह स्वीकार किया गया कि 2008 में सोनिया गांधी इस संस्था की अध्यक्ष थीं। उस समय कुल 9 संग्रह अलग किए गए थे और उन्होंने इन्हें अपने पास ले लिया था। बार-बार अनुरोध करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला, जब तक कि इस मुद्दे को सार्वजनिक रूप से नहीं उठाया गया। दिसंबर 2024 में कोई जवाब न मिलने पर, उन्होंने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से अपने शोध में मदद करने का अनुरोध किया। फिर, जनवरी 2025 में, कार्यकारी परिषद ने सोनिया जी से अनुरोध किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। आखिरकार, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस मामले को सार्वजनिक किया। कादरी को उम्मीद है कि वह इन संग्रहों को स्वायत्त संस्था को वापस कर देंगी।

बंगाल में विस चुनाव में टीएमसी का नया दांव

महात्मा गांधी के नाम पर राजनीति हुई तेज

» भाजपा को घेरने की तैयारी

» सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुकाबले ममता बनर्जी ने पेश किया संवैधानिक राष्ट्रवाद

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

कोलकता। बंगाल में अगले साल होने वाले विधान सभा चुनाव के लिए माहौल गरमाने लगा है। सता में बैठी टीएमसी सरकार विपक्षी पार्टी भाजपा को घेरने का कोई भी मौका छोड़ना नही चाहती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बड़ा राजनीतिक और वैचारिक बयान देते हुए राज्य सरकार की रोजगार योजना 'कर्मश्री' का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात परशर्म महसूस होती है कि राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के नाम को कल्याणकारी योजनाओं से हटाया जा रहा है।

ममता बनर्जी का इशारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम में किए गए कथित बदलावों की ओर था, जिसे लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। कर्मश्री योजना को महात्मा गांधी के नाम से जोड़कर ममता बनर्जी ने एक साथ कई निशाने साधे हैं। पहला, उन्होंने खुद को गांधीवादी मूल्यों की रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया है। दूसरा, केंद्र सरकार पर यह आरोप मजबूती से चस्पा किया है कि वह राष्ट्रपिता की विरासत को हाशिए पर डाल रही है। और तीसरा, ग्रामीण, गरीब और श्रमिक वर्ग के साथ एक भावनात्मक रिश्ता फिर से गढ़ने की कोशिश की है। यह वही वर्ग है जो कभी वाम मोर्चे की ताकत हुआ करता था और आज तृणमूल की राजनीति की रीढ़ है।

'कर्मश्री' योजना के तहत राज्य में 75 से 100 दिनों तक रोजगार मिलेगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'कर्मश्री' योजना के तहत राज्य में 75 से 100 दिनों तक रोजगार दिया जाता है और अब यह योजना महात्मा गांधी के नाम से जानी जाएगी। ममता बनर्जी ने भावुक अंदाज़ में कहा, मैं वास्तव में शर्मिंदा हूं। राष्ट्रपिता का नाम योजनाओं से हटाया जा रहा है। मैं किसी और को दोष नहीं देती, क्योंकि मैं इसी देश की नागरिक हूं। हम राष्ट्रपिता को भूलते जा रहे हैं, यह दुखद है।

भावनात्मक और वैचारिक मुद्दों से संचालित होती है राजनीति

इसके अलावा, ममता बनर्जी का यह फैसला सिर्फ एक योजना का नाम बदलने का एलान नहीं है, बल्कि यह आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की राजनीतिक पटकथा का पहला स्पष्ट अध्याय भी है। ममता बनर्जी जानती हैं कि बंगाल की राजनीति केवल विकास के आंकड़ों से नहीं, बल्कि भावनात्मक और वैचारिक मुद्दों से संचालित होती है। और गांधी से बड़ा प्रतीक भारतीय राजनीति में शायद ही कोई हो।

ममता का केंद्र सरकार पर परोक्ष हमला

उन्होंने केंद्र सरकार पर परोक्ष हमला करते हुए कहा कि अगर केंद्र महात्मा गांधी को सम्मान नहीं देगा तो बंगाल देगा। ममता ने कहा, अगर आप महात्मा गांधी का सम्मान नहीं करेंगे, तो हम करेंगे। अपने भाषण में ममता बनर्जी ने महात्मा गांधी के साथ-साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर, डॉ. भीमराव आंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल और लाल-बाल-पाल का भी उल्लेख किया। उन्होंने बंगाल की समावेशी संस्कृति की बात करते हुए कहा कि राज्य हर समुदाय और हर विचारधारा का सम्मान करता है। देखा जाये तो यह बयान ऐसे समय आया है जब MNREGA के नाम और पहचान को लेकर देशभर में राजनीतिक बहस चल रही है और तृणमूल कांग्रेस इसे केंद्र सरकार की इतिहास और प्रतीकों को बदलने की राजनीति बता रही है।

संविधान बनाम सत्ता, गांधी बनाम विचारधारा और राज्य बनाम केंद्र की धुरी की रणनीति

बहरहाल, आगामी चुनावों को देखते हुए ममता बनर्जी साफ तौर पर राजनीति को संविधान बनाम सत्ता, गांधी बनाम विचारधारा और राज्य बनाम केंद्र की धुरी पर ले जाना चाहती हैं। यह वही रणनीति है जिसने उन्हें पहले भी भाजपा के आक्रामक चुनावी अभियान के सामने खड़ा रखा। ममता जानती हैं कि बंगाल में सीधे हिंदुत्व की राजनीति को जवाब देना कठिन है, इसलिए वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और संवैधानिक राष्ट्रवाद का विकल्प पेश कर रही हैं।

Sanjay Sharma

editor.sanjaysharma
@Editor_Sanjay

जिद... सच की

मंदिरों में वीआईपी दर्शन सुविधा पर लगे रोक

सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों में वीआईपी दर्शन सुविधा को चुनौती देने वाली याचिका भले ही खारिज कर दी, किंतु इस याचिका पर कोर्ट द्वारा कही गई बातों की गूंज दूर तक जाएगी। यह गूंज केंद्र सरकार को विवश करेगी कि वह मंदिरों में हाने वाले वीवीआईपी दर्शन पर रोक लगाने वाला निर्णय लें।

मंदिरों में वीआईपी दर्शन सुविधा को रो कना चाहिए। यह मामला देश भर के मंदिरों में आम लोगों और वीआईपी के बीच भेदभाव के मुद्दे को उठाता है। वीआईपी दर्शन की सुविधा से आम लोगों को लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ता है, जबकि वीआईपी आसानी से दर्शन कर लेते हैं। के ंद्र की सरकार को इस ध्यान देना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों में वीआईपी दर्शन सुविधा को चुनौती देने वाली याचिका भले ही खारिज कर दी, किंतु इस याचिका पर कोर्ट द्वारा कही गई बातों की गूंज दूर तक जाएगी। यह गूंज केंद्र सरकार को विवश करेगी कि वह मंदिरों में हाने वाले वीवीआईपी दर्शन पर रोक लगाने वाला निर्णय लें। कोर्ट की ये गूंज आने वाले समय में मंदिरों के वीवीआईपी दर्शन कर रोक लगाने का रास्ता प्रशस्त करेगी। पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यह एक नीतिगत मामला है। इस पर केंद्र सरकार को विचार करना होगा। बेंच ने यह भी कहा कि वीआईपी के लिए ऐसा विशेष व्यवहार मनमाना है।

यह याचिका मंदिरों की तरफ से वसूले जाने वाले वीआईपी दर्शन शुल्क को समाप्त करने की मांग कर रही थी। पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि बेंच इस मुद्दे से सहमत है, लेकिन अनुच्छेद 32 के तहत निर्देश जारी नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, हालांकि हमारी राय है कि मंदिरों में प्रवेश के संबंध में कोई विशेष व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन हमें नहीं लगता कि यह अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का उपयुक्त मामला है। यह आदेश में दर्ज किया गया लेकिन मामला सरकार के विचार के लिए छोड़ दिया गया। पूर्व सीजेआई खन्ना ने कहा कि यह मामला कानून-व्यवस्था का प्रतीत होता है और याचिका इस पहलू पर होनी चाहिए थी। बेंच ने कहा, %हम स्पष्ट करते हैं कि याचिका खारिज होने से संबंधित अधिकारियों को जरूरत के हिसाब से कार्रवाई करने से नहीं रोका जाएगा। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, आज 12 ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। ये मनमाना और भेदभाव वाला है। यहां तक कि गृह मंत्रालय ने भी आंध्र प्रदेश से इसकी समीक्षा करने को कहा है। चूंकि, भारत में 60 प्रतिशत पर्यटन धार्मिक है, इसलिए ये भगदड़ की प्रमुख वजह भी है। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका विजय किशोर गोस्वामी ने डाली थी। उन्होंने मंदिरों में अतिरिक्त शुल्क लेकर %वीआईपी दर्शन% के चलन को आर्टिकल 14 के तहत समानता के अधिकार और आर्टिकल 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन बताया। उन्होंने दलील दी कि जो लोग इस तरह का शुल्क अदा करने में असमर्थ हैं, ये उनके खिलाफ भेदभाव है। याचिका में जोर देकर कहा गया था कि कई मंदिर 400 से 500 रुपये में लोगों के लिए विशेष दर्शन की व्यवस्था करते हैं। इससे आम श्रद्धालु और खासकर महिलाएं, स्पेशली एबल्ड लोग और सीनियर सिटिजंस को दर्शन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

नाभिकीय ऊर्जा में निजी क्षेत्र का रास्ता खुला

प्रमोद जोशी

संसद ने 'सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया विधेयक, 2025' को पारित कर दिया। इसे अंग्रेजी नामाक्षरों के आधार पर 'शांति-विधेयक' कहा गया है। हालांकि, कई विपक्षी सांसदों ने विधेयक को संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की थी, पर सरकार ने इसे राज्यसभा में चर्चा के लिए भेजकर जल्दी पास कराना उचित समझा। अब यह कानून बन जाएगा। दोनों सदनों की राजनीतिक बहसों पर ध्यान नहीं दें, तो यह स्पष्ट है कि यह कानून यूपीए सरकार में अमेरिका के साथ हुई 'न्यूक्लियर-डील' का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो अब अमेरिका के साथ संभावित व्यापार समझौते के साथ भी जुड़ा है। यह कानून अनायास ही नहीं बनाया गया है। कई कारणों से 'न्यूक्लियर डील' अपने अभीप्सित उद्देश्यों में पूरी तरह सफल नहीं हो सकी।

एक बड़ा अड़ंगा, संभावित दुर्घटना की क्षतिपूर्ति को लेकर था, जिसके लिए 2010 में पास हुए नागरिक दायित्व अधिनियम से विदेशी आपूर्तिकर्ता सहमत नहीं थे। 2008 में, भाजपा ने मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, जिसका एक कारण यह भी था कि 'न्यूक्लियर डील' में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, जिससे क्षतिपूर्ति हो सके। इस साल का बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने नाभिकीय ऊर्जा को लेकर कुछ बड़ी घोषणाएं की थीं। उन्होंने स्वदेशी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) विकसित करने के लिए 20,000 करोड़ रुपये के 'परमाणु ऊर्जा मिशन' की घोषणा की थी। 2033 तक इनमें से कम से कम पांच रिएक्टर चालू हो जाएंगे। भारत के 2047 तक 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा सुनिश्चित करने के बड़े लक्ष्य के लिहाज से यह महत्वपूर्ण है। उसके पहले पिछले साल जुलाई में नई सरकार के पहले बजट भाषण में उन्होंने कहा था कि सरकार भारत स्मॉल रिएक्टर (बीएसआर) की स्थापना, भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (बीएसएमआर) के अनुसंधान और विकास, तथा परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी।

भारत में परमाणु बिजली बनाने का काम अभी तक सरकारी कंपनी न्यूक्लियर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड करती है। अब नाभिकीय बिजली उत्पादन में निजी क्षेत्र का प्रवेश भी होगा, जिसमें विदेशी

कंपनियों की भागीदारी भी हो सकती है। यह घोषणा नाभिकीय ऊर्जा के मामले में भारत-अमेरिका संवाद फिर से कायम होने की ओर इशारा कर रही है। 2008 की न्यूक्लियर डील ने भारत और अमेरिका को काफी करीब कर दिया था, पर इसी डील ने दोनों के बीच खटास भी पैदा की थी। न्यूक्लियर डील होते वक्त लगता था कि भारत नाभिकीय ऊर्जा के लिए अपने दरवाजे खोलेगा, पर उस दिशा में प्रगति नहीं हुई, बल्कि सब कुछ धीमा पड़ गया। 2011 में जापान के फुकुशिमा एटमी बिजलीघर की दुर्घटना के बाद उससे जुड़े जोखिम को लेकर भी सवाल उठे। भारतीय संसद ने 2010 में सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट पास किया, जिसमें वे व्यवस्थाएं थीं, जो परमाणु दुर्घटना की स्थिति में मुआवजे का भार उपकरण सप्लाई करने वाली कंपनी पर डालती थीं। उस कानून की धारा 17 से जुड़े मसले पर दोनों देशों के बीच सहमति नहीं रही है। यह असहमति केवल अमेरिका के साथ ही नहीं थी, दूसरे देशों के साथ भी थी। 2010 में जब यह कानून पास हो रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी भी कड़ी शर्तें लागू करने की पक्षधर थी। बाद में यूपीए सरकार पर जब अमेरिकी दबाव पड़ा तो रास्ते खोजे जाने लगे। भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 1.5 प्रतिशत और उत्पादित बिजली का 3 प्रतिशत हिस्सा परमाणु ऊर्जा क्षेत्र से आता है। स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने, ग्रिड की स्थिरता में सुधार करने और 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए हाल के वर्षों में सरकार के एजेंडे में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र का निजीकरण करना प्रमुख रहा है। भारत के रूपांतरण के लिए परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन और विकास विधेयक, 2025, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, पुराने 1962 के कानून और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 दोनों को निरस्त करके उनका स्थान लेगा।

वर्ष 1962 का कानून परमाणु ऊर्जा के विकास और उपयोग के आधार प्रदान करता है, और 2010 का परमाणु दुर्घटना के मामले में दायित्व और मुआवजा देने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। नया कानून दो स्पष्ट जरूरतों से प्रेरित है। एक, कोयले पर आधारित ऊर्जा के स्थान पर अक्षय ऊर्जा क्षमता का निर्माण और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, नाभिकीय-क्षमता वृद्धि के लिए पूंजी की आवश्यकता।

आपराधिक मामलों के निपटान में देरी अन्याय जैसा

डॉ. के.पी. सिंह

एक दिवंगत रेलवे टीटीई को 50 रुपये की रिश्वतखोरी के आरोप से मुक्त होने में 40 साल लग गए, जिसके कारण अपने जीवन-काल में उन्हें सरकारी नौकरी, सम्मान और मानसिक शांति खोने का दंश झेलना पड़ा था। मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन में तैनात लिपिक, जागेश्वर प्रसाद अवधिया को 100 रुपये रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तारी के 39 वर्ष बाद सर्वोच्च न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया। वर्ष 2005 और 2006 के सबसे चौंकाने वाले निठारी सीरियल किलिंग मामलों में नवम्बर, 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने सुरेन्द्र कोली और पंढेर को भी दोषमुक्त कर दिया है। वस्तुत: भारत में आपराधिक मामलों के निर्णय में देरी आपराधिक न्याय प्रणाली में अन्तर्निहित है, जिसके परिणाम स्वरूप गिरफ्तार किए गए सभी लोगों में से 46 प्रतिशत से अधिक को विचाराधीन कैदियों के रूप में विभिन्न अवधियों के लिए जेलों में सजायाफ्ता दोषियों की तरह कष्ट सहने को मजबूर होना पड़ रहा है।

इस पृष्ठभूमि में, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकान्त द्वारा लम्बित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का एजेंडा तय करना प्रशंसनीय पहल है। 29 अक्टूबर, 2025 को भी आरोप निर्धारण में अत्यधिक देरी पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गम्भीर चिन्ता व्यक्त की गई थी और इस समस्या के समाधान के लिए समुचित दिशा-निर्देश निर्धारित करने हेतु भारत के महान्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल से सहयोग मांगा था। आपराधिक मामलों के निपटान में देरी महज आकस्मिक नहीं, जिसे दिशा-निर्देश बनाकर रोका जा सके, वास्तव में यह उभरती दरपेश परिस्थितियों से निपटने में संस्थागत विफलता का मामला है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के प्रकाशन 'भारत में अपराध-2023' के अनुसार, पिछले वर्ष के लम्बित 2,45,84,673 मामलों में इस वर्ष 8,25,681 और आपराधिक मामलों की बढ़ोतरी हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2023 के अन्त तक देश में कुल 2,54,10,354 आपराधिक मामले निचली अदालतों में लम्बित हो गए।

इस वर्ष न्यायालयों द्वारा 40,95,080 आपराधिक मामलों का ही निपटान सम्भव हो सका जबकि इस दौरान 49,20,771 नए मामले निर्णय के लिए अदालतों में प्राप्त हुए। इस प्रकार लम्बित मामलों की संख्या में प्रतिवर्ष औसतन 16 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। लम्बित आपराधिक मुकदमों के पीछे के कारणों को समझने के लिए गहन विश्लेषण और शोध की आवश्यकता है। इस बढ़ते रुझान को रोकने और लम्बित मामलों की संख्या को कम करने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति अपनाने की जरूरत है। इस रणनीति में निम्नलिखित आयाम शामिल किए जा सकते हैं, पहला, इस मिथक को तोड़ने की आवश्यकता है कि एक पुलिस थाना क्षेत्र के मुकदमों की सुनवाई के लिए एक ही ट्रायल कोर्ट हो सकता है। लम्बित मुकदमों की संख्या के आधार पर एक थाना क्षेत्र में एक से अधिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाने चाहिए।

कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रत्येक ट्रायल कोर्ट में ढांचागत सुविधाओं के साथ-साथ कम से कम तीन स्टेनोग्राफर और दो लोक अभियोजकों की तैनाती का प्रावधान हो। जब तक नियमित पीठासीन अधिकारियों, अभियोजकों, सचिवीय कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो जाती और अदालत कक्ष नहीं बन जाते, तब तक जिला जज को अदालतों के लिए भवन किराए पर लेने के लिए और अस्थायी अदालतों के संचालन हेतु सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार दिया जा सकता है। दूसरा, कई राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में एक ही न्यायाधीश आपराधिक और सिविल दोनों क्षेत्राधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। यदि क्षेत्राधिकार विभाजित कर दिया जाए और विभिन्न प्रकृति के मामलों से निपटने के लिए अलग-अलग मजिस्ट्रेट/सिविल जज नियुक्त कर दिए जाएं तो इससे मुकदमों का शीघ्र निपटान सम्भव होगा। कुछ राज्यों में यह प्रथा लागू भी है। तीसरा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा 359 में संशोधन करके 'समझौता योग्य मामलों' की सूची में विस्तार किया जा सकता है और 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय सभी अपराधों को समझौता योग्य अपराध घोषित करके उनका 'शीघ्र निपटान' सुनिश्चित किया जा सकता है।

भारत में अपराध, 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 में केवल 3,03,802 छोटे आपराधिक मामलों में ही पक्षकारों द्वारा समझौता किया गया जो कुल पंजीकृत मामलों का लगभग एक प्रतिशत है। चौथा, बीएनएसएस में प्रावधान है कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध और सामाजिक-आर्थिक अपराधों संबंधी मामलों को छोड़कर बाकी सभी अपराधों में जहां 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, पक्षकार आपसी सहमति से मुकदमों का निपटारा कर सकते हैं जिसे 'प्ली-बार्गेनिंग' की संज्ञा दी गई है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में केवल 42,318 मामलों का ही प्ली-बार्गेनिंग के माध्यम से निपटान किया जा सका था। प्ली-बार्गेनिंग के सम्बन्धित प्रावधानों में संशोधन करके प्ली-बार्गेनिंग करने वाले अपराधी के सिर से अपराधी का टैग हटाया जा सकता है। इसके अलावा, पक्षकारों को यह भी छूट हो कि आपराधिक कार्यवाही के प्रत्येक चरण में वे प्ली-बार्गेनिंग की प्रक्रिया अपनपाकर अपने मुकदमों का फैसला करवा सकें। पांचवां, आपराधिक मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने को बीएनएसएस में कई प्रावधान शामिल किए गए हैं।

किशमिश और बादाम

रात को पानी में 10 से 12 किशमिश और 6 से 7 बादाम भिगो कर रख दें। सुबह खाली पेट बादाम और किशमिश का सेवन करें इससे भी कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट इनका नियमित सेवन करें, ध्यान रहे कि अगर आपको शुगर है तो किशमिश का सेवन ना करें।

अलसी के बीज

अलसी के बीज भी बढ़ते कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत लाभदायक हैं। आप अलसी के बीजों का सेवन करें, या फिर अलसी के बीजों का पाउडर बनाकर रोजाना इसका सेवन करें। अलसी का थोड़ा पाउडर लेकर उसे एक गिलास छाछ में मिला लें। इसे अच्छी प्रकार से मिलाने के बाद इसका सेवन करें7 अलसी को आप अपने सब्जी में भी इस्तेमाल करें।

आंवला और एलोवेरा का जूस

रोजाना सुबह खाली पेट, एक चम्मच आंवला के रस में एक चम्मच एलोवेरा का रस मिलाकर इसका नियमित सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटाया जा सकता है। आंवला में विटामिन सी और साइट्रिक एसिड उच्च मात्रा में पाया जाता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण है।

कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए करें ये सेवन

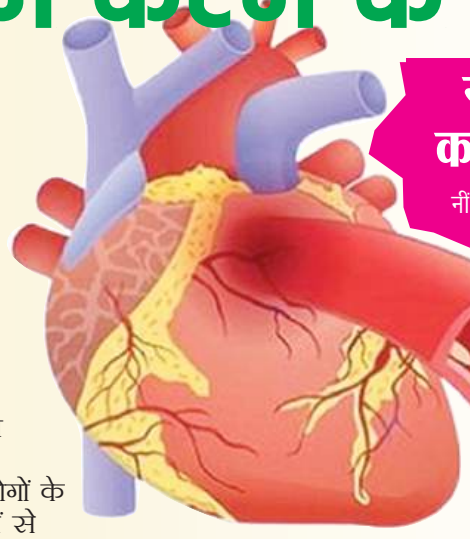

हमारे रक्त में खराब यानी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का अधिक स्तर कई गंभीर रोगों के प्रमुख जोखिम कारकों में से एक है। यह ब्लड प्रेशर के स्तर को बढ़ाता है, साथ ही हृदय रोग जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक और फेलियर आदि का भी कारण बनता है। यह क्रोनिक किडनी रोगों का भी कारण बन सकता है। इसलिए गंभीर रोगों से बचने और स्वस्थ रहने के लिए खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करना बहुत जरूरी है। लेकिन शरीर में अच्छा कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ाएं और खराब कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करें, इसको लेकर लोग काफी परेशान रहते हैं।

विटामिन सी वाले फल खाएं

याद रखिये, जितने भी विटामिन सी और साइट्रिक एसिड युक्त फल हैं वो सभी कोलेस्ट्रॉल के रोगियों के लिए बहुत लाभदायक हैं जैसे आंवला, अनार, नींबू, संतरा, मौसमी आदि जो भी इस प्रकार के खट्टे अर्थात साइट्रिक एसिड युक्त फल और सब्जी हैं वो सभी आपके लिए अच्छी हैं।

कच्चा लहसुन

कच्चा लहसुन कोलेस्ट्रॉल के रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद है। सुबह खाली पेट एक या दो कच्चे लहसुन की कली खाने से धमनियों में जमा कोलेस्ट्रॉल कम होने लगता है। आपको किसी दवाई की जरुरत नहीं है, यह नुस्खा कम से कम 15 से 30 दिन तक इस्तेमाल करें आपको फायदा खुद नजर आने लगेगा।

नींबू और काला नमक

नींबू में साइट्रिक एसिड बहुत प्रचुर मात्रा में होता है जिसकी वजह से यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने में चमत्कारी रुप से लाभकारी है। सुबह खाली पेट एक गिलास पानी में एक नींबू का रस निचोड़ें और इसमें अपने काला नमक स्वादानुसार मिला लें। अब इस घोल का सेवन करें।

अखरोट

अखरोट एनर्जी का भंडार है। रोजाना चार अखरोट खाने से हमारे शरीर को त्वरित एनर्जी मिलती है साथ ही इसमें कैल्शियम, मैंगनीशियम, ओमेगा थ्री, फाइबर, मैंगनीज, कॉपर और फॉसफोरस जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। रोजाना सुबह चार अखरोट खाने से रक्तवाहनियों में जमा कोलेस्ट्रॉल पिघलने लगता है और यह आपके खराब कोलेस्ट्रॉल को वापस यकृत तक भेजने में बहुत मददगार है इसलिए रोजाना चार अखरोट खाने की आदत डालिये।

काले चने

कला चना अक्सर ही घरों में सब्जी के रूप में खाया जाता है। काले चने में विटामिन ए, बी, सी, डी, कैल्शियम, फाइबर, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल उच्च रहता है उन्हें काले चनों का सेवन करना चाहिए। रात को एक मुट्ठी काले चने पानी में भिगोकर छोड़ दें और सुबह इन चनों को खाली पेट खाएं। साथ ही जिस पानी में चने भिगोये थे उसे फेंकें नहीं बल्कि उस पानी को भी पियें।

हंसना मना है

1 मुर्गी ने बत्तख से शादी कर ली, मुर्गा बोला- हम मर गये थे क्या? मुर्गी- मैं तो तुमसे ही शादी करना चाहती थी पर मोम-डैड चाहते थे लड़का नेवी में हो?

मम्मी-किचन से जरा छोटी वाली गिलास ले लाना...पिंटू-मुझे यहां पर कहीं भी गिलास दिखाई नहीं दे रहा है ... मम्मी-चूल्हा दिखाई दे रहा है.. पिंटू-हां...मम्मी- अब एक काम कर चूल्हा जला...अब उसके ऊपर अपना मोबइल रख दे...तब दिखेगी गिलास।

संता बस में खड़ा था ब्रेक लगा तो एक लड़की पर जा गिरा, लड़की- बद्तमीज ...क्या कर रहे हो, संता- आईटीआई और आप? लड़की ने की चप्पलों से पिटाई।

पति- क्या तुम्हें पता है कि गाने में इतनी ताकत होती है कि पानी भी गरम हो जाता है पत्नी- हां हां जरूर, क्यों नहीं जानती, अब तुम यही सोच लो अगर तुम्हारा गाना सुन कर मेरा खून खौल सकता है, तो फिर पानी क्यों नहीं।

शशि-'ऑटोग्राफ देना कब बेहतर नहीं लगता?' विनोद-'जब पत्नी को चेक बुक पर देना पड़े।

कहानी | युवा पत्नी और चोर

सालों पहले एक गांव में सूरज नाम का किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान बूढ़ा था, लेकिन उसकी पत्नी जवान थी। इसी वजह से किसान की पत्नी दुखी रहती थी। वो हमेशा अपने ही जैसे जवान पुरुष से शादी करने की चाहत मन में रखती थी। महिला के मन की बात को एक चोर समझ गया। वो रोज महिला का पीछा करने लगा। एक दिन उसने किसान की पत्नी को ठगने के विचार से उसे एक झूठी कहानी सुनाई। चोर ने कहा, सालों पहले मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई थी। अब मैं अकेला हूं। मैं तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हो गया हूं और तुम्हें अपने साथ शहर ले जाना चाहता हूं। स्त्री यह सुनते ही खुश हो गई। वो फटाफट बोली, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मेरे पति के पास बहुत धन है। पहले मैं उसे ले आती हूं। उन पैसों से हम जीवनभर आराम से रहेंगे। यह सुनकर चोर ने कहा कि ठीक है तुम जाओ और लौटकर इसी जगह आना मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। स्त्री घर पहुंची, तो देखा कि पति गहरी नींद में था। महिला ने सारे जेवर और नकदी को पोटली में बांधा और चोर के पास चली गई। किसान की पत्नी को आते देखकर चोर के मन में हुआ, अब मैं बहुत जल्दी धनवान बनने वाला हूं। बस अब इस महिला से पीछा छुड़ाने की तरकीब निकालनी होगी। तभी किसान की पत्नी चोर के पास पहुंची। उसके पहुंचते ही दोनों दूसरे शहर की ओर निकल गए। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में एक नदी मिली। नदी को देखते ही चोर को एक तरकीब सूझ गई। वह महिला से बोला, देखो, नदी गहरी है। इसे मैं तुम्हें पार करवाऊंगा, लेकिन पहले मैं यह पोटली नदी के उस पार रखूंगा फिर तुम्हें साथ ले जाऊंगा। स्त्री को चोर पर पूरा विश्वास था उसने कहा, हां, ऐसा करना ठीक रहेगा। फिर चोर ने कहा, देखो, तुमने भारी जेवर पहने हैं। ये जेवर भी तुम मुझे दे दो, ताकि तुम्हें नदी पार करने में कोई बाधा न हो। यह सुनते ही किसान की पत्नी ने अपने सारे जेवर चोर को दे दिए। पोटली में बंधा धन और महिला के जेवर लेकर चोर नदी के पार चला गया। महिला उसके लौटने का इंतजार करती रही, लेकिन वो फिर कभी लौट कर नहीं आया। अब महिला को बहुत दुख हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन पछतावे के लिए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका सारा पैसा और जेवर लेकर चोर जा चुका था।

7 अंतर खोजें

पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेष रोजगार मिलेगा। अप्रत्याशित लाभ होगा। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। विवाद न करें। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें।

वृषभ फालतू खर्च होगा। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। वाणी पर नियंत्रण रखें। चिंता रहेगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। नवीन मुलाकातों से लाभ होगा। आमदनी बढ़ेगी।

मिथुन विवाद से क्लेश होगा। शारीरिक कष्ट संभव है। बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे। यात्रा सफल रहेगी। आपसी मतभेद, मनमुटाव बढ़ेगा।

कर्क घर-बाहर तनाव रहेगा। विवाद को बढ़ावा न दें। जल्दबाजी न करें। नई योजना बनेगी। नए अनुबंध होंगे। किसी मामले में कटु अनुभव मिल सकते हैं। लोभ, लालच से बचें।

सिंह धर्म-कर्म में रुचि रहेगी। यात्रा सफल रहेगी। धन प्राप्ति सुगम होगी। कानूनी बाधा दूर होकर लाभ होगा। पूँजी निवेश बढ़ेगा। संतान के कामों से खुशी होगी।

कन्या चोट, चोरी व विवाद आदि से हानि संभव है। पुराना रोग उभर सकता है। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। परिवार की स्थिति अच्छी रहेगी। रचनात्मक काम करेंगे।

तुला शारीरिक कष्ट से बाधा संभव है। भागदौड़ रहेगी। घर-परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। राजकीय सहयोग मिलेगा। कार्यकुशलता सहयोग से लाभान्वित होंगे।

वृश्चिक चोट व रोग से बाधा संभव है। बेचैनी रहेगी। भूमि व भवन संबंधी बाधा दूर होगी। रोजगार मिलेगा। संतान के स्वास्थ्य में सुधार होगा। सोचे कामों में मनचाही सफलता मिलेगी।

धनु पार्टी व पिकनिक का आनंद मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग को सफलता मिलेगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। नए कार्यों, योजनाओं की चर्चा होगी। लाभदायी समाचार आएंगे।

मकर पुराना रोग उभर सकता है। भागदौड़ रहेगी। दु-खद समाचार मिल सकता है। धैर्य रखें। अस्वस्थता बनी रहेगी। खुद के प्रयत्नों से ही जनप्रियता एवं सम्मान मिलेगा।

कुम्भ प्रयास सफल रहेंगे। प्रशंसा प्राप्त होगी। धन प्राप्ति सुगम होगी। वाणी पर नियंत्रण रखें। लाभ होगा। व्यवसाय अच्छा चलेगा। कार्य क्षेत्र में नई योजनाओं से लाभ होगा।

मीन पुराने संगी-साथियों से मुलाकात होगी। शुभ समाचार प्राप्त होंगे। व्यवसाय ठीक चलेगा। लाभ होगा। परिश्रम का पूरा परिणाम मिलेगा। वाणी पर नियंत्रण रखें।

बॉलीवुड | मन की बात

धर्मेंद्र की फिल्म 'इक्कीस' का ट्रेलर देख भावुक हुए सनी देओल

फिल्म इक्कीस अगले साल सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म का ट्रेलर पहले भी आ चुका है। मगर, आज शुक्रवार को इसका फाइनल ट्रेलर जारी किया गया है, जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। सनी देओल ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से ट्रेलर रिलीज किया है। इसमें अपने दिवंगत पिता की झलक देख वे भावुक हो गए हैं। सनी देओल ने इक्कीस का फाइनल ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा है, लव यू पापा। इसके साथ तीन रेड हार्ट इमोजी बनाए हैं। आगे लिखा है, सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता की सच्ची कहानी देखिए। एक हीरो, जो सिर्फ 21 साल की उम्र में अमर हो गया, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। यह फिल्म 01 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म इक्कीस में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा लीड रोल में हैं। यह बड़े पर्दे पर उनकी डेब्यू फिल्म है। अगस्त्य फिल्म में सेना के सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का किरदार निभा रहे हैं। वहीं, धर्मेंद्र उनके पिता की भूमिका में हैं। ट्रेलर में धर्मेंद्र को देखकर अच्छा लगता है। ट्रेलर में फिल्म के बाकी सितारे- जयदीप अहलावत, समीर भाटिया और सिकंदर खेर भी नजर आते हैं। फिल्म इक्कीस पहले 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होने वाली थी। मगर, बाद में मेकर्स ने रिलीज डेट में बदलाव कर दिया। अब यह पहली जनवरी को दस्तक देगी। सनी देओल के पोस्ट पर नेटिजन्स रिएक्टर करते हुए धर्मेंद्र को याद कर रहे हैं और लिख रहे हैं, धर्मेंद्र की बहुत याद आ रही है। बता दें कि 24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया।

14 साल साल बाद टीवी पर वापसी करेंगे अक्षय, व्हील ऑफ फार्च्यून शो करेंगे होस्ट

अक्षय कुमार फिल्मों में लोगों को एंटरटेन करने के बाद अब टीवी पर गेम खिलाने के लिए आ रहे हैं। एक बार फिर अक्षय कुमार बड़े पर्दे के अलावा छोटे पर्दे पर नजर आने वाले हैं। वो एमी अवॉर्ड विनर टीवी गेम शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' भारत में लेकर आ रहे हैं। अक्षय कुमार इस शो को होस्ट करेंगे। सोनी टीवी पर आएगा शो

आठ बार एमी अवॉर्ड जीतने वाला अमेरिका का नंबर वन टेलीविजन गेम शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' अब भारत में सोनी टीवी और सोनी लिव पर प्रसारित होने के लिए तैयार है। अक्षय कुमार शो में बतौर होस्ट शामिल होंगे। सोनी टीवी की ओर से इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया गया, दुनिया के सबसे बड़े टेलीविजन गेम शो ने भारत को नमस्ते कहा है। इसके साथ ही मेकर्स ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अक्षय कुमार इस शो को होस्ट करेंगे। हालांकि, अभी तक शो की रिलीज डेट और कंटेस्टेंट के नाम सामने नहीं आए हैं।

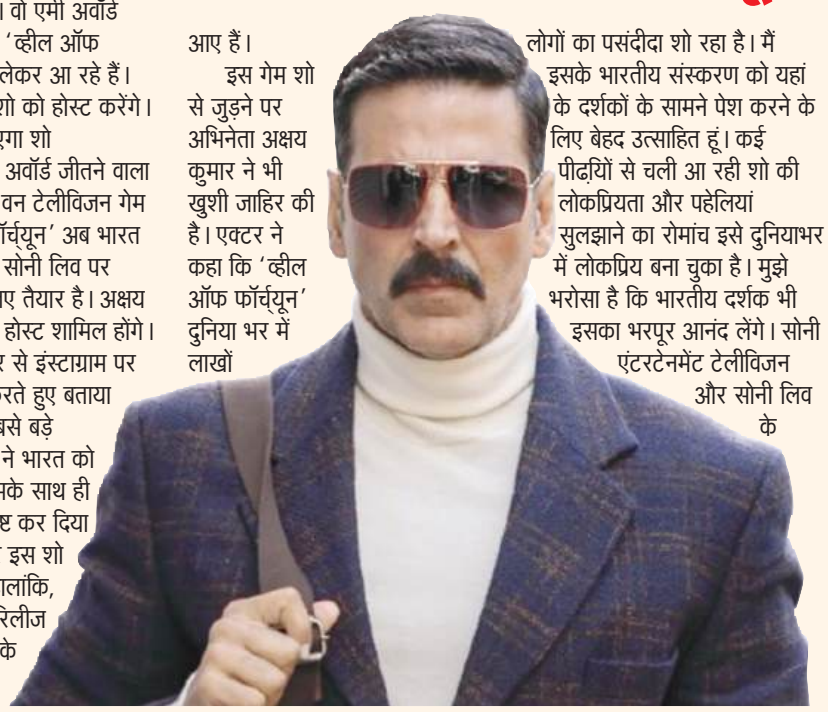

इस गेम शो से जुड़ने पर अभिनेता अक्षय कुमार ने भी खुशी जाहिर की है। एक्टर ने कहा कि 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' दुनिया भर में लाखों लोगों का पसंदीदा शो रहा है। मैं इसके भारतीय संस्करण को यहां के दर्शकों के सामने पेश करने के लिए बेहद उत्साहित हूं। कई पीढ़ियों से चली आ रही शो की लोकप्रियता और पहेलियां सुलझाने का रोमांच इसे दुनियाभर में लोकप्रिय बना चुका है। मुझे भरोसा है कि भारतीय दर्शक भी इसका भरपूर आनंद लेंगे। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव के जरिए 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' भारतीय दर्शकों को अलग-अलग प्लेटफार्म्स पर शानदार तरीके से जोड़ेगा।

ये अक्षय की टीवी पर वापसी है

अक्षय कुमार इससे पहले 'खतरों के खिलाड़ी' के पहले, दूसरे और चौथे सीजन को भी होस्ट कर चुके हैं। चौथा सीजन साल 2011 में आया था। इसके अलावा वो एक कॉमेडी शो लेकर भी आए थे। हालांकि, ये ज्यादा दिन तक नहीं चला था। हाल ही में अक्षय करण जौहर के साथ 'पिच टू गेट रिच' में भी नजर आए थे। अब अक्षय दुनिया के सबसे पॉपुलर शो को लेकर आ रहे हैं।

खुदा हाफिज फेम शिवालिका ओबेरॉय ने किया प्रेग्नेंसी का ऐलान

शिवालिका ओबेरॉय और मशहूर निर्देशक-निर्माता अभिषेक पाठक की जिंदगी में जल्द ही एक नया और बेहद खास अध्याय जुड़ने वाला है। शादी के करीब तीन साल बाद यह कपल अपने पहले बच्चे का स्वागत करने की तैयारी कर रहा है। इस खुशखबरी को दोनों ने बेहद खूबसूरत अंदाज में सोशल मीडिया के जरिए साझा किया, जिसके बाद से ही फिल्म इंडस्ट्री और फैंस की तरफ से लगातार बधाइयों का सिलसिला जारी है।

शिवालिका और अभिषेक ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें कपल की खुशी साफ झलक रही है। तस्वीरों में शिवालिका लाल रंग की ड्रेस में नजर आ रही हैं और उनके हाथ में नन्हे बेबी सॉक्स हैं, जो आने वाली नई जिंदगी का प्रतीक हैं। वहीं अभिषेक पाठक काले रंग की शर्ट में शिवालिका को थामे हुए दिखाई दे रहे हैं। क्रिसमस ट्री के सामने खड़ी यह जोड़ी बेहद सुकून और प्यार से भरी नजर आती है।

एक दूसरी तस्वीर में दोनों ने क्रिसमस ऑर्नामेंट पकड़ा हुआ है, जिस पर लिखा है- बेबी पाठक आने वाला है। इस फोटो में कपल ने अपने चेहरे छुपा रखे हैं, लेकिन उनकी खुशी शब्दों से कहीं ज्यादा तस्वीरों में झलक रही है। इस खास पोस्ट के साथ कपल ने कैप्शन में लिखा कि उनकी लव स्टोरी अब अपने सबसे खूबसूरत पड़ाव पर पहुंच रही है और उनकी दुनिया में एक छोटी-सी ब्लेसिंग जुड़ने वाली है।

शिवालिका और अभिषेक की प्रेम कहानी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दोनों की पहली मुलाकात साल 2020 में फिल्म 'खुदा हाफिज' के सेट पर हुई थी। इस फिल्म को अभिषेक पाठक ने प्रोड्यूस किया था और शिवालिका इसमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आई थीं। काम के दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई, जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। इसके बाद अभिषेक ने टर्की में हॉट एयर बैलून के नीचे बेहद रोमांटिक अंदाज में शिवालिका को प्रपोज किया था। फरवरी 2023 में दोनों ने गोवा में अपने करीबी दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में शादी कर ली। शादी के वक्त भी कपल ने सोशल मीडिया पर लंबा-सा नोट लिखकर अपनी खुशियां फैंस के साथ साझा की थीं। अगर करियर की बात करें तो अभिषेक पाठक बॉलीवुड के जाने-माने नाम हैं।

अजब-गजब | ये है जवानों का रिटायरमेंट हाउस

इस केयर होम में दूर-दूर से आराम करने आ रहे युवा, सोने के अलावा नहीं कोई काम!

आजतक आपने बुजुर्गों के लिए बनाए गए केयर होम के बारे में सुना होगा। ये वो जगह होती है, जहां रिटायरमेंट के बाद बुजुर्ग आराम करते हैं। यहां उन्हें सिर्फ आराम करना होता है। ना किसी तरह का स्ट्रेस और ना ही कोई दूसरा काम। सिर्फ आराम ही आराम। लेकिन अब इस कॉन्सेप्ट के जैसा ही यूथ रिटायरमेंट होम खुल चुका है। जी हां, यहां युवा आराम करते हैं। वैसे युवा तो अपनी जिंदगी के स्ट्रेस से परेशान हैं, वो यहां आकर रिलैक्स कर रहे हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि वाकई इस होम में युवाओं की भीड़ लगी हुई है।

इस रिटायरमेंट होम का मालिक खुद एक 25 साल का युवा है। उसके पेरेंट्स बुजुर्गों के लिए केयर होम चलाते हैं। अपने पेरेंट्स द्वारा बुजुर्गों के लिए खोले गए रिटायरमेंट होम को देख उसे युवाओं के लिए ऐसा ही कुछ करने का आइडिया सुझा। इसके बाद उसने यूथ रिटायरमेंट होम बनाया, जो अब खूब चर्चा में है। यहां आने वाले गेस्ट्स तब तक सो सकते हैं, जब तक उनका मन हो। कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। इस होम के ओनर ने बताया कि आज के दौर में नब्बे और सन दो हजार में जन्में लोग तीस से पहले ही स्ट्रेस से भरे हैं। उन्हें कहीं रिलैक्स करने का मौका नहीं मिलता। घर, ऑफिस की जिम्मेदारी ने उन्हें बुढ़ापे से पहले ही थका दिया है। ऐसे में ये होम उनके लिए एक सपने जैसा है। यहां आकर कई युवा महीने भर रहते हैं। इसके बदले उन्हें सिर्फ 44 हजार रुपए चुकाने होते हैं। इसमें उनका रहना, तीन टाइम का खाना, एक आरामदायक माहौल शामिल है। युवाओं का सपनों का ये आशियाना मलेशिया के कुआलालुंपुर में स्थित है। आठ एकड़ में खुले इस होम में रहने के दौरान गेस्ट्स को कुछ भी करने की जरुरत नहीं है।

यूथ रिटायरमेंट होम का ये आइडिया युवाओं को काफी पसंद आ रहा है। यहां 9 से 5 के जॉब की टेंशन नहीं है। आपको आराम से घर का बना खाना मिलेगा, आप चाहे तो बागवानी कर सकते हैं। या चाहें तो बस लेटे रह सकते हैं। बता दें कि चीन में अब युवा ऐसे कांसेप्ट को काफी पसंद कर रहे हैं। सक्सेस के लिए भूखे युवा अब थक चुके हैं। अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ आराम करने का मन है। ऐसे में इस तरह के रिटायरमेंट होम युवाओं को एक उम्मीद दे रहे हैं। इसके फाउंडर ने बताया कि पहले ही महीने में पूरा का पूरा होम बुक हो चुका है। अब वो फरवरी की बुकिंग ले रहे हैं।

कभी सोचा है दाएं हाथ से ही क्यों होता है हैंडशेक? चौंका देगी वजह

जब भी लोग एक-दूसरे से मिलते हैं, तो आमतौर पर दाहिने हाथ से ही हाथ मिलाते हैं। यह आदत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। दुनियाभर में करीब 88 से 90 प्रतिशत लोग हैंडशेक के लिए दाहिना हाथ ही आगे बढ़ाते हैं, जबकि सिर्फ 8 से 10 प्रतिशत लोग ही बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हाथ मिलाने के लिए दाहिना हाथ ही क्यों चुना जाता है? इसके पीछे कई दिलचस्प कारण हैं। आइए जानते हैं। दाहिने हाथ से हैंडशेक करने का एक बड़ा कारण धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, जहां बाएं हाथ को अशुभ माना जाता है और शुभ कार्य दाहिने हाथ से करने की परंपरा रही है। इसके अलावा, प्राचीन काल में लोग दाहिने हाथ से ही हथियार रखते थे, ऐसे में सामने वाले के सामने दाहिना हाथ बढ़ाना यह दर्शाता था कि उनके पास कोई हथियार नहीं है और वे शांति का संदेश दे रहे हैं। बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि अभिवादन के लिए दाहिने हाथ का प्रयोग करना चाहिए, जिससे यह आदत और मजबूत हो जाती है। इतिहास में झांकें तो प्राचीन रोम में लोग एक-दूसरे पर भरोसा जताने के लिए कलाई या भुजा पकड़ते थे, जो समय के साथ बदलकर आज के हैंडशेक का रूप बन गया। चूंकि दुनिया में ज्यादातर लोग दाहिने हाथ से काम करते हैं, इसलिए अभिवादन के समय स्वाभाविक रूप से दाहिना हाथ ही आगे बढ़ता है। दाहिने हाथ से हाथ मिलाना आपसी भरोसे, सम्मान और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है, और हाथ मिलाने की पकड़ व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी दर्शाती है। समय के साथ, हैंडशेक अभिवादन का एक अहम और सार्वभौमिक तरीका बन चुका है।

अपने सहयोगियों के बयान से फिर फंस गई बीजेपी

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के वायरल वीडियो से बवाल

» शिंदे ने बीएमसी चुनावों में सीटों के मामले में भाजपा को छकाया

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। भाजपा को अपने सहयोगी दलों के बयान में फं स गई है। एक तरफ बिहार में उसके सहयोगी हम पार्टी ने अभी संपन्न हुए विधान सभा चुनावों के परिणाम पर दिए बयान पर घमासाप मचा है तो वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना ने निकाया चुनाव की सीटों पर मांग करके भाजपा को बगलें झांकने को मजबूरकर दिया है। बता दें सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक मंच से मगही भाषा में अपने बयान दिए। इस वीडियो के सामने आने के बाद चुनावी व्यवस्था और लोकतंत्र पर बहस तेज हो गई है।

एक वीडियो में जीतन राम मांझी कहते हुए सुने जा रहे हैं कि, 2020 में 2600 वोट से हार रहे थे, तब कोशिश कर जीत दिला दी गई। इस बार 1600 वोट से हारे, लेकिन हमें बताया ही नहीं गया। उन्होंने उस समय के जिलाधिकारी का भी जिक्र किया, जो वर्तमान में त्रिपुरा में पदस्थ बताए जा रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष लगातार वोट चोरी और चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाता रहा है। केंद्रीय मंत्री का यह बयान राजनीतिक गलियारों में नई बहस को जन्म दे रहा है।

जिलाधिकारी जीत मैनेज करा देते हैं : नारायण मांझी

वायरल वीडियो के बारे में जानकारी देते हुए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के गयाजी जिलाध्यक्ष नारायण मांझी ने कहा कि इस तरह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी मिली है, लेकिन उन्होंने अभी इसे नहीं सुना है। सुनने के बाद ही वे इस पर टिप्पणी कर पाएंगे। जानकारी के अनुसार, गया जिले के बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के मोहनपुर प्रखंड में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सभा को संबोधित करते हुए यह बात कही थी।

मुंबई भाजपा अध्यक्ष ने गठित की समिति

मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित सतम ने बीएमसी चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु 20 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति के अध्यक्ष अमित सतम के अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, राज्य विधानसभा अध्यक्ष राहुल नरवेकर, कई राज्य मंत्रिमंडल मंत्रियों और विधायकों को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

शिंदे ने 2017 वाले फॉर्मूले को लागू करने की कर दी डिमांड

महाराष्ट्र में आगामी बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों के लिए शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच सीट बंटवारे की बातचीत में एक बड़ा झटका लगा है। सूत्रों के अनुसार, दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच हुई बैठक में शिंदे सेना ने 2017 के बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों के परिणामों का हवाला देते हुए उन सभी 84 सीटों की मांग की, जो उस समय अविभाजित शिवसेना ने जीती थीं। हालांकि, भाजपा ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। भाजपा का तर्क है कि 2017 की राजनीतिक परिस्थितियों और वर्तमान स्थिति में काफी अंतर है। भगवा पार्टी ने कहा कि शिंदे सेना और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के बीच सीधा मुकाबला महायुति गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकता है। भाजपा ने कहा कि शिंदे सेना को केवल वही सीटें आवंटित की जाएंगी जहां उसकी सबसे मजबूत उपस्थिति है और सीट बंटवारा जीत की संभावना के फार्मूले के आधार पर तय किया जाएगा। बीएमसी की कुल 227 सीटों में से 77 सीटों पर दोनों पार्टियों के बीच विवाद है। उम्मीद है कि दोनों पक्षों के वरिष्ठ नेता अगले दो दिनों में गतिरोध को सुलझाने के प्रयास करेंगे।

इल्तिजा ने नीतीश के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत

» हिजाब विवाद पर महबूबा की बेटी नाराज

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

श्रीनगर। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ कोठी बाग पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में उन्होंने इस घटना को मुस्लिम महिलाओं और भारतीय महिलाओं की गरिमा पर हमला करार दिया है। शिकायत में बताया गया कि कुछ दिन पहले बिहार के एक सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक युवा मुस्लिम डॉक्टर नुसरत परवीन का नकाब सार्वजनिक रूप से हटाया था।

इस दौरान बिहार के उपमुख्यमंत्री और अन्य लोगों की हंसी और बेरूखी ने स्थिति को और बढ़ा दिया। इल्तिजा ने कहा कि यह कार्रवाई सिर्फ एक मुस्लिम महिला पर हमला नहीं बल्कि हर भारतीय महिला की स्वायत्तता, पहचान और गरिमा पर हमला है। उन्होंने सरकार और अधिकारियों से तत्काल एफआईआर दर्ज करने और उचित कानूनी कार्रवाई करने की अपील की। बाद भारत के अन्य हिस्सों में मुस्लिम महिलाओं के हिजाब हटाने की घटनाओं में वृद्धि हुई है, और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

भारत का लगातार सातवीं बिना ठोस विकल्प के हिस्सा क्यों छोड़े

टी20 सीरीज पर कब्जा

» दक्षिण अफ्रीका को अंतिम मैच में 30 रन से हराकर 3-1 से जीती सीरीज

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

अहमदाबाद। भारत ने पांचवां टी20 मुकाबला 30 रन से जीत लिया। इसी के साथ टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 3-1 से हराकर लगातार सातवीं टी20 सीरीज अपने नाम की। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की अर्धशतकीय पारियों की मदद से 20 ओवर में पांच विकेट पर 231 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 20 ओवर में आठ विकेट पर 201 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई। भारत ने विश्व चैंपियन बनने के बाद से सात टी20 सीरीज और एशिया कप अपने नाम किया। भारत 2023 से टी20 में अजेय है।

दिलचस्प बात यह है कि भारत की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यह 35 मैचों में 21वीं जीत है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा 22 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले जीते हैं। 232 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफ्रीका की शुरुआत अच्छी हुई थी। पहले विकेट के लिए 69 रनों की साझेदारी हुई जिसे वरुण चक्रवर्ती ने तोड़ा। वहीं, क्विंटन डिकॉक ने अपने करियर का 18वां अर्धशतक जड़ा और 65 रनों की दमदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे। उन्हें बुमराह ने अपना शिकार बनाया। इसके बाद अफ्रीका का बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। इससे पहले, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 63 रनों की साझेदारी हुई, जिसे कॉर्बिन बॉश ने तोड़ा। इस दौरान अभिषेक ने टी20 अंतरराष्ट्रीय में 1000 रन भी पूरे कर लिए। अभिषेक सबसे कम गेंदों में यह कारनामा करने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने यह उपलब्धि 528 गेंदों में हासिल की। दूसरे स्थान पर कप्तान सूर्यकुमार यादव आए हैं, जिन्होंने 573 गेंदों में 1000 रन पूरे किए थे।

विजय हजारे ट्रॉफी : बंगाल की तेज गेंदबाजी की अगुआई करेंगे मोहम्मद शमी

कोलकाता। विजय हजारे ट्रॉफी वनडे टूर्नामेंट के लिए बंगाल की टीम घोषित हो गई है। शमी लंबे वक्त से राष्ट्रीय टीम से बाहर चल रहे हैं, लेकिन उन्हें लगातार बंगाल की टीम में जगह मिल रही है। चोट से उबरने के बाद बंगाल की तरफ से घरेलू क्रिकेट में शानदार वापसी की। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में वर्तमान सत्र में अभी तक सभी प्रारूप में 36 विकेट लिए हैं। शमी विजय हजारे ट्रॉफी में बंगाल टीम के लिए तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुआई करेंगे। भारतीय घरेलू सत्र की शुरुआत रणजी ट्रॉफी से हुई जिसमें शमी ने चार मैच में 18.60 के औसत से 20 विकेट लिए। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी20 टूर्नामेंट में भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा और सात मैचों में 14.93 के औसत से 16 विकेट हासिल किए। बंगाल की टीम में भारतीय तेज गेंदबाज आकाश दीप और मुकेश कुमार भी शामिल हैं।

हरियाणा : सुरजेवाला

» कांग्रेस सांसद ने कहा- एक लाख करोड़ मिले तो राज्य चंडीगढ़ पर दावा छोड़ देगा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चंडीगढ़। हरियाणा-पंजाब के बीच चंडीगढ़ को लेकर चल रही राजनीतिक बहस के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार हरियाणा को नई राजधानी बसाने के लिए एक लाख करोड़ रुपये का फंड दे दे तो हरियाणा चंडीगढ़ पर दावा छोड़ने को तैयार है। सुरजेवाला ने यह बात सेक्टर-35 स्थित कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बातचीत में कही।

सुरजेवाला ने कहा कि चंडीगढ़ के मुद्दे पर हरियाणा की स्थिति पूरी तरह साफ है। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत चंडीगढ़ का बंटवारा 60:40 के अनुपात में पंजाब और हरियाणा के बीच किया गया था। ऐसे में हरियाणा का चंडीगढ़ पर 40 प्रतिशत कानूनी और सांविधानिक अधिकार बनता है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब यह अधिकार स्पष्ट रूप से मौजूद है, तो हरियाणा बिना किसी ठोस विकल्प के अपना हिस्सा क्यों छोड़े।

मनीष तिवारी की राय से बनाई दूरी

चंडीगढ़ से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी की उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए, जिसमें तिवारी ने चंडीगढ़ को मूल रूप से पंजाब की राजधानी बताया था, सुरजेवाला ने कहा कि मनीष तिवारी अपने दृष्टिकोण से सही हो सकते हैं लेकिन हरियाणा का भी चंडीगढ़ में वैध हिस्सा है। उन्होंने दो टूक कहा कि अगर यह हिस्सा छोड़ने की बात होती है, तो हरियाणा को नई राजधानी बसाने के लिए एक लाख करोड़ रुपये देने होंगे।

बीजेपी पार्षद ने लगाया गलत हलफनामा

» लखनऊ के वार्ड-73 फैजुल्लागंज का चुनाव रद्द, सपा के ललित तिवारी निर्वाचित घोषित

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। भाजपा के फैजुल्लागंज तृतीया से पार्षद रहे प्रदीप कुमार शुक्ला उर्फ टिंकू शुक्ला की पार्षदी निरस्त। ललित तिवारी को पार्षद घोषित किया। नगरीय निकाय सामान्य चुनाव-2023 के अंतर्गत वार्ड संख्या-73, फैजुल्लागंज (तृतीय नगर निगम, लखनऊ) से जुड़ी चुनाव याचिका को स्वीकार कर लिया गया है।

न्यायालय के आदेश के अनुसार 13.05.2023 को निर्वाचित घोषित किए गए पार्षद प्रदीप कुमार शुक्ला का निर्वाचन निरस्त कर दिया गया है। साथ ही, सपा से प्रत्याशी रहे ललित तिवारी को उक्त वार्ड से निर्वाचित घोषित किया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। भाजपा पार्षद पर गलत जानकारी का आरोप लगा था।

आश्वासन नहीं, आंदोलन होगा: व्यापारी

» नगर निगम मुख्यालय पहुंच कर दिया धरना

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। राजधानी में ट्रेड लाइसेंस का शुल्क बढ़ाने पर शहर के सैकड़ों व्यापारी आज (शनिवार को) नगर निगम मुख्यालय पहुंच गए हैं। वे मुख्यालय के सामने बैठकर धरना दे रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि नगर निगम जबरदस्ती कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के हस्तक्षेप के बाद फीस बढ़ाने का फैसला पिछले साल वापस ले लिया था, लेकिन अब फिर से उसे लागू किया जा रहा है।

लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्रा ने कहा- अब आश्वासन नहीं सुना जाएगा। एक साल का आश्वासन नहीं मानेंगे। आंदोलन को दुनिया पहचानती है। हम आंदोलन करेंगे। पहले ही व्यापारी तमाम तरीके का टैक्स दे रहा है, जिनकी कोई सुविधा नहीं मिल रही है। ऐसे में फिर व्यापारियों को ही टारगेट किया गया है। इसी के विरोध में लखनऊ व्यापार मंडल सहित अन्य संगठनों से जुड़े व्यापारियों में आक्रोश है।

शीतकालीन सत्र बना प्रदूषण सत्र : जयराम रमेश

कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोले- संसद में प्रदूषण पर चर्चा क्यों नहीं की गई

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। संसद में प्रदूषण पर चर्चा न होने को लेकर सियासी कोहराम मचा हुआ है। विपक्ष ने एनडीए सरकार को घेरते हुएकहा कि सरकार जनहित के मुद्दों पर गंभीर नहीं है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि हाल ही में समाप्त हुआ संसद का शीतकालीन सत्र सरकार की इस मुद्दे पर व्यवस्थित बहस करने की अनिच्छा के कारण प्रभावी रूप से प्रदूषण सत्र में तब्दील हो गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रमेश ने कहा कि संसद में सरकार की प्रतिक्रिया से उन्हें गहरा सदमा लगा, जिसमें उन्होंने प्रदूषण और फेफड़ों से संबंधित बीमारियों के बीच किसी भी संबंध से इनकार किया।

कांग्रेस नेता ने कहा कि यह शीतकालीन सत्र नहीं, बल्कि प्रदूषण सत्र था। मैं उस समय स्तब्ध रह गया जब सरकार ने कल संसद में यह कहकर जवाब दिया कि प्रदूषण और फेफड़ों की समस्याओं के बीच कोई संबंध नहीं है। रमेश ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश भर में, विशेष रूप से उत्तर भारत में, जहां प्रदूषण का स्तर हफ्तों से गंभीर बना हुआ है, बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर विस्तृत चर्चा की बार-बार मांग की थी।

राहुल ने वायु प्रदूषण पर चर्चा की मांग की थी

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने वायु प्रदूषण पर चर्चा की मांग की थी। हम लोकसभा और राज्यसभा में इस पर बहस चाहते थे। कांग्रेस नेता ने सरकार के इस दावे को खारिज कर दिया कि विपक्ष द्वारा व्यवधान डालने से प्रदूषण पर बहस नहीं हो सकी। उन्होंने बताया कि विपक्ष की मांगों के बावजूद लोकसभा को इस मुद्दे पर चर्चा किए बिना अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। दुर्भाग्य से, लोकसभा में ही सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की गई।

सत्ताधारी पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन

उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए, रमेश ने जोर देकर कहा कि चर्चा न होने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार का यह बयान कि कांग्रेस के कारण प्रदूषण पर चर्चा नहीं हो सकी, गलत है। मैं इसे पूरी तरह से खारिज करता हूं। रमेश की ये टिप्पणी संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा कांग्रेस पर संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान वायु प्रदूषण पर प्रस्तावित चर्चा को बाधित करने का आरोप लगाने के बाद आई है। रिजिजू ने दावा किया था कि सरकार पूरे दिन की बहस के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष के व्यवधान के कारण ऐसा करने से रोक दिया गया।

इंडो-यूएस न्यूक्लियर डील का विरोध क्यों किया

सांसद जयराम रमेश ने सरकार से तीखा सवाल पूछा। उन्होंने बिल पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि साल 2008 में भारत और अमेरिका के बीच एक परमाणु करार हुआ था। इसका विरोध सबसे ज्यादा बीजेपी ने ही किया था। उन्होंने कहा, उस वक्त बीजेपी ने कहा था कि परमाणु ऊर्जा का कोई भविष्य नहीं है इसलिए इसका हम इसका विरोध कर रहे हैं। जबकि उसी बिल की बदौलत अमेरिका और भारत के बीच कई रास्ते खुले थे। परमाणु ऊर्जा रूपांतरण विधेयक बिल भी उसी का नतीजा है। जयराम रमेश ने सदन को बताया कि 20 साल के शासनकाल में कांग्रेस ने क्या-क्या किया। उन्होंने साल 2014 के बाद के भारत का जिक्र करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने देश को बताया कि 2014 के बाद ही सबकुछ हुआ है। खासतौर पर स्पेस और परमाणु कार्यक्रम। लेकिन हकीकत इससे अलग है। कांग्रेस के शासनकाल में ही इन दोनों सेक्टर्स को काफी बढ़ावा दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी से मौजूदा सरकार को सबक सीखना चाहिए, क्योंकि वह भी कांग्रेस के परमाणु कार्यक्रम का जिक्र कर चुके हैं।

असम में बड़ा ट्रेन हादसा, राजधानी एक्सप्रेस से कट गए आठ हाथी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

गुवाहाटी। असम में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। ट्रेन संख्या 20507 डीएन सैरांग-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस हाथियों के झुंड से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेन का इंजन और पांच डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि, ट्रेन में सवार किसी भी यात्री कोचोट नहीं आई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये 8 हाथियों का झुंड था, जिसमें से ज्यादातर मारे गए हैं। यह घटना उस स्थान पर घटी जहां हाथियों का गलियारा नहीं है। लोको पायलट ने हाथियों के झुंड को देखकर आपातकालीन ब्रेक लगाए। ट्रेन फिर भी हाथियों से टकरा गए और हादसा हो गया।

ट्रेन हादसा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के लुमडिंग डिवीजन में हुआ। दुर्घटना स्थल गुवाहाटी से करीब 126 किलोमीटर दूर है। रेस्क्यू ट्रेन अधिकारियों के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हो चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक, पटरी से उतरने और पटरियों पर हाथियों के शव मिलने के कारण ऊपरी असम और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों के लिए रेल सेवाएं

फिलहाल बंद हैं. वन विभाग के सूत्रों ने बताया के ट्रेन हादसे में 8 हाथियों की मौत हो गई है। हाथी का छोटा बच्चा इस हादसे में घायल हुआ है, जिसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रेन के पटरी से उतरने और हाथियों के शरीर के अंगों के पटरियों पर बिखरे होने के कारण ऊपरी असम और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों के लिए रेल सेवाएं फिलहाल डायवर्ट कर दी गई हैं। इस डिवीजन से गुजरने वाली ट्रेनों को यूपी लाइन से डायवर्ट किया जा रहा है. असम में ट्रेन की पटरी के मरम्मत का काम जारी है।

मान सरकार के समझाने पर माने आक्रोशित किसान

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चंडीगढ़। पंजाब के किसानों ने प्रस्तावित रेल रोको आंदोलन को लेकर अपना फैसला बदल दिया है। 20 दिसंबर को होने वाला यह विरोध प्रदर्शन राज्य सरकार के आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया है। किसान नेता सरवन सिंह भंडार ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार शाम को सरकार के साथ बैठक हुई, जिसमें किसानों को आश्वासन दिया गया कि बिजली संशोधन विधेयक पंजाब में लागू नहीं किया जाएगा।

सरकार ने स्मार्ट बिजली मीटर लगाने के संबंध में भी सकारात्मक आश्वासन दिया और कहा कि ऐसे मीटर राज्य में नहीं लगाए जाएंगे। किसान नेताओं ने स्पष्ट किया कि आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय सरकार के आश्वासनों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आंदोलन वापस नहीं लिया गया है, बल्कि केवल स्थगित किया गया है। इस बीच, किसानों की लंबित मांगों पर चर्चा करने के लिए किसान प्रतिनिधियों और सरकार के बीच 22 दिसंबर को एक और बैठक निर्धारित की गई है।

किसी को भी हिंसा करने पर छोड़ा नहीं जाएगा : मो. यूनुस

» बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या में शामिल सात आरोपी गिरफ्तार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

ढाका। बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले के वालुका इलाके में हिंदू धर्म के अनुयायी युवक दीपू चंद्र दास (27) की पीट-पीटकर हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने बताया कि रैपिड एक्शन बटालियन ने इस जघन्य घटना में शामिल सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी से पूछताछ जारी है और मामले की गहन जांच की जा रही है।

मोहम्मद यूनुस ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की सांप्रदायिक

हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्य सलाहकार के अनुसार आरएबी 14 ने विशेष अभियान चलाकर विभिन्न स्थानों से सात संदिग्धों को हिरासत में लिया। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि यह घटना न केवल मानवता के खिलाफ अपराध है, बल्कि सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा।

चेन्नई के बीएसएनएल ऑफिस में भीषण आग

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। शनिवार सुबह चेन्नई के अन्ना सलाई स्थित बीएसएनएल भीषण आग लग गई। आग लगने से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि यह घटना छुट्टी वाले दिन हुई, जिसके कारण ऑफिस बंद था और कोई वहां नहीं था। वरना बड़ा हादसा हो सकता था अधिकारियों ने बताया कि उन्हें अन्ना सलाई स्थित बीएसएनएल कार्यालय में आग लगने की सूचना सुबह करीब 9:30 बजे मिली।

सूचना मिलते ही अग्निशमन और बचाव की टीम मौके पर पहुंची। करीब एक घंटे की अधिक समय तक आग बुझाने की कोशिश जारी रही। आग को कंट्रोल में करने के लिए कम से कम 5 दमकल गाड़ियां और 10 मेट्रो वाटर टैंकर लगाए गए। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट हो सकता है। पुलिस के अनुसार, दूसरी मंजिल के एक कमरे में रखी बैटरी में विस्फोट होने का संदेह है, जिससे आग भड़की होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि आग बिजली के तारों के जरिए फैल गई और इमारत की तीसरी, चौथी और छठी मंजिल तक पहुंच गई। हालांकि घटना की पूरी जांच के बाद ही आग लगने के सटीक कारणों का पता चल पाएगा। आग लगने से बीएसएनएल परिसर में चल रही सेवाओं में बाधा उत्पन्न हुई। कार्यालय में रखे उसके सर्वर प्रभावित हुए, जिसके परिणामस्वरूप ऑनलाइन भुगतान सेवाएं अस्थायी रूप से बाधित हुईं।

महाराष्ट्र की छवि बिगाड़ रहे राज्य के मंत्री : सुप्रिया

एनसीपी के दो मंत्रियों पर लगे गंभीर आरोपों पर सियासी बवाल, एनसीपी शरद पवार गुट ने भाजपा को घेरा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी (अजित पवार गुट) के दो मंत्रियों पर लगे गंभीर आरोपों को लेकर सियासी बवाल मच गया है। एनसीपी (शरद पवार गुट) की वरिष्ठ नेता सुप्रिया सुले ने इस पूरे मामले पर तीखी प्रतिक्रि या देते हुए कहा कि ऐसे घटनक्रम महाराष्ट्र की छवि के लिए बुरा है और दिल्ली तक में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि राज्य में आखिर चल क्या रहा है।

सुप्रिया सुले ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार में शामिल दो बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगे हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में उनसे लोग पूछ रहे थे कि महाराष्ट्र में एक और मंत्री का विकेट गिर गया? उनके मुताबिक, इस तरह की बातें राज्य की छवि को खराब करती हैं और जनता में गलत संदेश जाता है। उन्होंने साफ कहा कि यह स्थिति किसी भी तरह से अच्छी नहीं कही जा सकती। मनरेगा के नाम को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सुप्रिया सुले ने कहा कि महात्मा गांधी का नाम हटाने का फैसला गलत है.

माणिकराव कोकाटे मामले पर चिंता

पूर्व मंत्री माणिकराव कोकाटे को लेकर सुप्रिया सुले ने कहा कि किसानों के बारे में जिस तरह की बातें कही गईं, वह दुर्भाग्यपूर्ण हैं. फिलहाल कोकाटे अस्पताल में भर्ती हैं और उन्हें सही इलाज मिलना चाहिए, यह जरूरी है।

उनका कहना है कि इससे न सिर्फ प्रतीकात्मक नुकसान हुआ है, बल्कि आगे चलकर राज्यों को मिलने वाली फंडिंग पर भी असर पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि इस फैसले से राज्य सरकारों को नुकसान होगा और गरीबों से जुड़ी योजनाओं पर भी असर पड़ सकता है।

किसी का पहनावा उसका निजी विषय

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़े बुर्का विवाद पर सुप्रिया सुले ने संवेदनशील रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि किसी भी परिवार की परंपरा और पहनावा उसका निजी विषय होता है, घूंघट लेना हो या बुर्का पहनना, यह परिवार की अपनी परंपरा है, नीतीश कुमार एक वरिष्ठ नेता हैं और इस तरह के विवादों से हमें दुख होता है।

गठबंधन पर स्थानीय नेता ही फैसला लेंगे

एनसीपी (अजित पवार गुट) और शरद पवार गुट के संभावित गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर सुप्रिया सुले ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में स्थानीय नेता ही फैसला लेंगे। उन्होंने बताया कि पवार साहब पहले ही कह चुके हैं कि इस पर निर्णय जमीनी स्तर पर लिया जाएगा।

स्वामी 4 पीएम न्यूज नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक **संजय शर्मा** द्वारा आस्था प्रिंटर्स, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से मुद्रित एवं 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से प्रकाशित। **महाराष्ट्र कार्यालय**:- 2 जी, कृष्णा कुटीर सागरिका CHS जुहू तारा रोड जुहू- मुंबई- 400049। **संपादक** - संजय शर्मा, **विधि सलाहकार**: सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, मोहम्मद हैदर, **वित्तीय सलाहकार**: संदीप बंसल, **कार्टूनिस्ट**: हसन जैदी, **दूरभाष**: 0522- 4078371 | **Email**: daily4pm@gmail.com | **website**: www.4pm.co.in | **RNI-UPHIN/2015/62233** डाक पंजी. सं- SSP/LW/NP-495/2018-2020 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।